REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 8 | MAY - 2025

भारत में सुशासन की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका और चुनौतियों का एक विश्लेषण

डॉ. रिंकल
सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र), डॉ. बी. आर. अंबेडकर लॉ कॉलेज, कुरुक्षेत्र.

सारांश:

'सुशासन' के विभिन्न तरीकों ने प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों से लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को कम करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। सरकार जो राजनीतिक समुदाय के आंतरिक और बाहरी हितों को साधने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने की प्रशासनिक मशीनरी और संस्थागत व्यवस्था में सुधार करती है और शासन को विकसित करने के लिए कार्य करती है जो लोगों के लिए 'अच्छा महसूस' करने में मदद करती है। सरकार ऐसी प्रणाली विकसित करती है जो लोगों की जरूरतों और समस्याओं का मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छा होने की सुविधा प्रदान करती है। जैसा कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं, "यह कम या ज्यादा सरकार का सवाल नहीं है, लेकिन यह किस तरह की सरकार है जो हमें शासन के मुद्दे पर ले जाती है।" इस प्रकार, इस पेपर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है जिसका उद्देश्य चुनौतियों के साथ-साथ भारत में सुशासन की अवधारणा और भूमिका का विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द : - शासन, कल्याण, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता।

भूमिका

'गवर्नेंस' शब्द का पहली बार इस्तेमाल 12वीं शताब्दी में फ्रांस में किया गया था, जहां यह एक तकनीकी शब्द था, जो बैलेज या बेलीविक्स के प्रशासन को डिजाइन करता था। जैसा कि सरकार शब्द के साथ है, यह लैटिन शब्द "रूडर" से आया है जो "स्टीयरिंग" के विचार को व्यक्त करता है। शासन ने इस प्रकार एकता पर ध्यान केंद्रित किया-हितों की विशिष्टता नहीं (अवस्थी और महेश्वरी 1982)। मोटे तौर पर, हम कह सकते हैं कि 'शासन' एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो परामर्श, संवाद, आदान-प्रदान और आपसी सम्मान के माध्यम से सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करती है और कुछ मामलों में, विभिन्न और कुछ समय के अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच सुसंगतता है। . "सुशासन" कैसे विकसित होता है? नियमों और नियमों के बीच संबंध एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। इतिहास, रीति-रिवाज, कानून, समाज और राजनीतिक अर्थव्यवस्था देश में शासन को प्रभावित करते हैं, उनके प्रदर्शन के लिए नियमों को ध्यान में रखते हैं। सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का सापेक्ष खुलापन और सरकार के निर्णय लेने और जनता के साथ बातचीत में पूर्वानुमान की डिग्री, जवाबदेही का विकास शासन के विकास पर उपयोगी परिप्रेक्ष्य हैं (बघल, सी.एल और योगेंद्र कुमार, 2006)।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने "शासन" शब्द को मोटे तौर पर परिभाषित किया है, "आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक प्राधिकरण का प्रयोग सभी स्तरों पर देश के मामलों का प्रबंधन करता है। इसमें तंत्र, प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों को दूर करते हैं। भागीदारी, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पारस्परिकता और राज्य की जिम्मेदारी के मूल सिद्धांतों पर

आधारित होने के कारण सुशासन और मानव अधिकार की अवधारणाएं पारस्परिक रूप से मजबूत हैं। मानवाधिकार और सुशासन साथ-साथ चलते हैं और एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। अच्छा मानवाधिकार वातावरण प्रदान करने से सुशासन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। यानी सतत सामाजिक और राजनीतिक विकास। मानवाधिकार और सुशासन एक दूसरे से बहुआयामी रूप से जुड़े हुए हैं। जहां सुशासन का उद्देश्य सरकार और राजनीतिक संस्थानों को बनाना है, यह आम जनता को उनके लिए बनने वाली राजनीति और कानून के बारे में जागरूक होने के बुनियादी मानवाधिकारों के साथ सशक्त बनाने में मदद करता है। सुशासन' की बहु-आयामी धारणा को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न कल्याणोन्मुख शासकीय अभिकरणों द्वारा किये गये प्रयत्नों का 'समग्र रूप' है। इस प्रकार यह एक 'समग्र सूचकांक' है जिसमें आर्थिक सुधार, वैधानिक स्वतंत्र नियामक तंत्र का निर्माण जैसे पैरामीटर शामिल हैं जो व्यापक समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी 'शासी एजेंसियां' सरकार, प्रेस, दबाव समूह, ई-गवर्नेंस, गैर-सरकारी संगठन और वैश्वीकरण हैं (बुल, बेनेडाइट और डिस्माउंट, एम.सी. नील, 2006)। 'सुशासन' के लिए वातावरण। इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रशासनिक पदानुक्रम से संबंधित अधिकारियों के बीच काफी पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्कता की भावना विकसित हुई है।

सुशासन पर बहुआयामी विचार

न्यायपालिका, जिसे भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रकार के पक्षपात, गैर-संबद्धता और लोगों के लिए वास्तविक न्याय को छोड़कर, समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित है। अक्सर यह देखा गया है कि न्यायपालिका कभी-कभी मीडिया या दबाव समूहों से प्रभावित होती है, परिणामस्वरूप न्याय की भावना से विचलित हो जाती है। यह भी देखा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का भी सरकार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। मसलन, एसवाईएल, सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को पंजाब सरकार द्वारा अब तक भी लागू नहीं किया गया है. जनता के लिए सुशासन विकसित करने में इस प्रकार की प्रवृत्ति सदैव 'गीली कम्बल' सिद्ध होती रही है।

इसलिए, यह 'सुशासन' पर बहुआयामी अध्ययन से स्पष्ट है जो विभिन्न लेखकों और शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए विभिन्न दृष्टिकोणों और दृष्टिकोणों को इंगित करता है। उन्होंने विभिन्न समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है और 'सुशासन' के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के 'कारण-प्रभाव संबंध' स्थापित करने का प्रयास किया है। इससे व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक, लचीला और बदलते परिदृश्य में मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। 'सुशासन' की अवधारणा को मजबूत करना है ताकि बदलते परिदृश्य में इस धारणा को चुनौतियों का सामना करना पड़े। बदलते परिदृश्य के अनुसार 'सुशासन' के हर पहलू की समीक्षा की जानी है। तभी सुशासन की अवधारणा लोगों के लिए सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यह ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के सपनों को पूरा करना भी सुनिश्चित करेगा और देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी और गैर-आदिवासी संस्कृति के बीच 'सांस्कृतिक अंतराल' को भरने में भी मदद करेगा।

सुशासन की प्रकृति एवं विस्तार

आजादी के बाद से, 'नौकरशाही' समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित लोगों के लिए सरकार द्वारा व्युत्पन्न सार्वजनिक नीतियों को तैयार करने और क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नौकरशाही के कार्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के दायरे में होते हैं, लेकिन नौकरशाही हमेशा अवांछनीय राजनीतिक दबाव के अनुसार काम करती रही है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रशासनिक पदानुक्रम में इन 'नौकरशाहों' की जवाबदेही में काफी विचलन देखा जाता है (अरोड़ा, रमेश 2006)। हालांकि, हाल के वर्षों में, इस दिशा में एक परिदृश्य बदल रहा है क्योंकि वैश्वीकरण शासन/प्रशासनिक हेक्स की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए अधिक कार्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें राष्ट्रीय/प्रशासनिक प्रणाली पर वैश्वीकरण का प्रभाव दुनिया भर में है, जिस तरह से राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रणाली वैश्वीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तन का जवाब दे रही है, और सर्वोत्तम अभ्यास की पहचान जो राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रणाली कर सकती है अन्य मुद्दों के वैश्वीकृत विश्व में संचालन के नए तरीके को अपनाने के लिए अपनाएं (साहनी और उमा मेडुरी, 2007)।

ई-गवर्नेंस, जिसका तात्पर्य लैन (लोकल एरिया नेटवर्क), डब्ल्यूएसी, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल सेल और अन्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग से है, अपेक्षित जानकारी तक पहुंच प्रदान करने, सरकारी आधिकारिक अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, जनता को बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए जवाबदेह है। अधिकारियों के साथ, परिवहन का संचालन करना और सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन पेश करना। समय आ गया है, जब ई-गवर्नेंस सार्वजनिक अधिकारियों के बीच रिश्वत प्रणाली पर बातचीत के दायरे की पेशकश

की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अनुकूल साबित होगा, विवेकाधीन शक्ति और निर्णय लेने की प्रक्रिया के मानकीकरण को समाप्त कर देगा। इससे पारदर्शिता, प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के रहस्य से पर्दा हटाने, बहु-स्तरीय जवाबदेही और गैर-करने, गलत करने, पंक्ति-कूदने, पक्ष लेने या विरोध करने जैसी प्रचलित घटनाओं का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। अब ई-गवर्नेंस को व्यापक रूप से गुणवत्ता, दक्षता और प्रभावशीलता में परिवर्तनकारी सुधार, विकसित और विकासशील दोनों देशों में ई-गवर्नेंस के वितरण में ध्यान देने योग्य प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी गई है (आर.के.सप्रू और युधिष्ठर, 2014)।

आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून। 2005, समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित लोगों के लिए काफी हद तक तथ्यात्मक आंकड़ों को जानने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। यह भारत के नागरिकों के लिए विभिन्न अधिकारों में से एक 'लैंडमार्क' अधिकार है। इसके कार्यान्वयन के बाद से, इसने सरकारी मशीनरी की स्थिति को समझने का मार्ग प्रशस्त किया है, वह कारक जो विकास में सुधार करता है, सार्वजनिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं और बाधाएं। इसके अलावा, आरटीआई ने सरकार की नागरिक केंद्र योजनाओं के कामकाज, विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं, भ्रष्टाचार के स्तर आदि को समझने का मार्ग प्रशस्त किया है। आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, एक आवधिक मूल्यांकन किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाइयों की 'तथ्यात्मक तस्वीर' जानने के लिए काम किया (माथुर, कुलदीप, 2008)।

मीडिया देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुशासन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा वाहन है, जो रूपों को ग्रहण करने में सक्षम है, जो मालिश के साथ विशेषता है और लोगों की एक बड़ी संख्या को तेजी से, प्रभावी ढंग से और लागत प्रभावी ढंग से कवर करता है। हमने देखा है कि मीडिया जनहित के किसी भी मुद्दे के बारे में 'जनमत निर्माण' के इंजन का स्रोत है। यह नीतिगत मामलों पर न्यायपालिका, सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने, सार्वजनिक और निजी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित करने के लिए एक उत्प्रेरक बल प्रदान करता है।

विभिन्न मोर्चों पर 'सुशासन' विकसित करने के लिए दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेड यूनियनों, पेशेवर संघों, छात्र संघों, उपभोक्ता मंचों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कई दबाव समूह हैं जो 'विवेकपूर्ण निर्णय लेने' के लिए 'संग्रहित सौदेबाजी' के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोगों के लिए समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित हैं। वैश्वीकरण के तहत सुशासन की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए, जैन, आरबी (2005) कहते हैं कि वैश्वीकरण ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को दी गई दृश्यता के संबंध में बहुत कम प्राप्त किया है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, दिशा बदल रही है, क्योंकि वैश्वीकरण-शासन प्रशासनिक गठजोड़ की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए अधिक कार्य दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में मुद्दों ने ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दुनिया भर में राष्ट्रीय/सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली पर वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव शामिल है, जिस तरह से प्राकृतिक प्रशासनिक प्रणालियां वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान द्वारा लाए गए परिवर्तनों का जवाब दे रही हैं जो राष्ट्रीय प्रशासनिक हैं। सिस्टम वैश्वीकृत दुनिया के बदलते परिदृश्य में आकार लेने के लिए अपना सकता है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को विनियमित करने के लिए रचनात्मक सुधारों के लिए काफी दबाव लाया है (इस्साक एन.ओबासी, 2006) यह एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे के रूप में उभर रहा है, और 'विनियमन' जैसे रूपों को जन्म दिया है बदलते परिदृश्य के अनुसार लें। इस प्रक्रिया ने पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता, नौकरशाही में सुधार, सुशासन के मूल घटक के साथ-साथ राजनीतिक मूल्यों को एक नया आयाम दिया है जो इसे सूचित कर सकते हैं। दूसरी ओर, सुधार जो कई विकसित और साथ ही विकासशील देशों में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है, साथ ही वैश्विक राजनीति और वैश्विक शासन के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता, वांछनीयता और संभावना के बारे में एक राजनीतिक बहस भी होती है।

वर्तमान परिवेश में सुशासन की भूमिका

विकेंद्रीकरण और सुशासन की प्रक्रिया का सकारात्मक संबंध है। सुशासन के विभिन्न पहलुओं को प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रभाव, अब प्रशासनिक के साथ-साथ कॉर्पोरेट जगत में भी एक व्यापक प्राथमिकता बन गया है। 'वैश्वीकरण काल' की शुरुआत के बाद से, लोकतांत्रिक योजना में एक विकल्प बनाना अनिवार्य हो गया है, ताकि निर्णय लेने में कठोर प्रणाली लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी हो। पहले कठोर राजनीतिक वातावरण के तहत शक्ति और बंद व्यवस्था की एकाग्रता ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को पक्षपाती और असंतुलित बनाने के लिए जन्म दिया है। विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक नीति के निर्माण में खामियों को विकसित करने के लिए इस प्रकार की कठोर व्यवस्था को भी जन्म दिया गया है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि 'पंचायती राज व्यवस्था' में सत्ता का विकेंद्रीकरण जमीनी

स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास कार्यक्रमों के लिए 'रामबाण' साबित हुआ है। इस संदर्भ में, विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 'विकेंद्रीकृत लोकतंत्र' के रूप में सत्ता के 'विकेंद्रीकरण' ने अधिक जवाबदेही, सर्वसम्मति-उन्मुख, पारदर्शी, समन्वय, जवाबदेह, और कार्यान्वयन के मोर्चे पर लचीलापन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत नियमित रूप से समय-समय पर फीडबैक लेना अनुकूल सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर, नागरिक समाज जो समितियों की सदस्यता के माध्यम से नीति और परियोजना प्रस्ताव को प्रभावित कर सकता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे ज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है और नीतियों, परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संवादात्मक नियम नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। नागरिक समाज मानव अधिकारों, हकदारी और उत्तरदायित्वों के उल्लंघन और लोगों की नब्ज के बारे में सरकार, और समाज में 'सुशासन' को बहाल करने के लिए किसी कार्यक्रम या नीति के पक्ष में या उसके खिलाफ जनमत जुटाने के खिलाफ "प्रहरी" के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्रवाई के लिए जवाबदेह है और पूर्वानुमानित आर्थिक और सामाजिक नीतियों, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज का हिस्सा बनने की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित एक स्वच्छ प्रशासन का आयोजन करने में सक्षम है। भारत के लिए विशिष्ट संबंधित क्षेत्रों के रूप में, रे, विनायत (2013) जनसंख्या वृद्धि, मानव संसाधनों की गुणवत्ता और स्टॉक, ऊर्जा तक पहुंच को सूचीबद्ध करता है।

सतत विकास के लिए भी सुशासन प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और गुंजाइश दोनों है। सामान्य चिंता के कुछ क्षेत्रों में समुद्री और नदी तट के मुद्दे, ट्रांस-बाउंडिंग पर्यावरण प्रभाव, और जैव-संसाधनों का प्रबंधन, प्रौद्योगिकी साझा करना और सतत विकास के अनुभवों को साझा करना शामिल हैं। 'सुशासन' विकसित करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि समाज के विभिन्न स्तरों से संबंधित लोगों से समय-समय पर जवाबदेही के साथ अपनी नीतियों के निर्माण और निष्पादन के लिए सरकारों की भूमिका की समय-समय पर समीक्षा की जाए। तभी हम वांछित परिणाम प्राप्त करने की स्थिति में होंगे।

निष्कर्ष

सुशासन के अध्ययन और उसके विविध आयामों-परंपरा और आधुनिकता के आधार पर बदलते परिदृश्य के अनुरूप निरंतरता और परिवर्तन का संकेत मिलता है। परिवर्तन की दर समय-समय पर बदलती रही है। ऐतिहासिक अतीत सुशासन की धारणा के अपने "प्रचार" को दर्शाता है जो समय-समय पर बदलता रहा है, लेकिन धारणा की मूल भावना अब तक नहीं बदली है। सुशासन के सभी लक्षणों का उद्देश्य 'लोगों का कल्याण' है। सुशासन के कई आयामों में न्यायपालिका, मीडिया, प्रेस, विधायी, ई-गवर्नेंस, आरटीआई अधिनियम शामिल हैं। और जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण ने समाज में प्रतिकूल वातावरण से उत्पन्न चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने के लिए एक उपकरण के रूप में 'सुशासन' को विकसित करने के लिए संचयी रूप से काम किया है। यह प्रेस या अन्य प्रकार का मीडिया या दबाव समूह या नागरिक समाज हो सकता है- 'सुशासन' के इन एजेंटों का मूल कार्य एक सामाजिक स्थिरता स्थापित करना है ताकि पूरी व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी, सतर्क और हर मोर्चे पर जवाबदेह प्रत्येक कार्य योजना को जमीनी स्तर तक पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि हम सतत विकास की स्थिति प्राप्त कर सकें। इससे लोगों की आवश्यकता के अनुसार मौजूदा और भविष्य के 'परिवर्तनों' के प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होने की भी उम्मीद है। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 'सुशासन' की अवधारणा भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 'अच्छा रखने' को सुनिश्चित करेगी।

अंत में, 'सुशासन' के मंत्र के लिए एक कठोर प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है, जिस दिशा में आज की सरकार सही रास्ते पर दिख रही है और यहां भाजपा सरकार के लिए बढ़ती कीमतों, बिजली की कमी, दुर्दशा के लिए असली परीक्षा है। किसानों की समस्या, मध्यम और निम्न आय वर्ग की गंभीर समस्याएं, नक्सली हिंसा में वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, भूमि अधिग्रहण के कारण उजड़े लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समस्या, सेवा क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का स्थानांतरण, हाल ही में आरक्षण के नाम पर, हरियाणा में जाति-आधारित हिंसा, हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र द्वारा आत्महत्या, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में देश-विरोधी गतिविधियाँ भाजपा सरकार के सामने वर्तमान चुनौतियों में से कुछ हैं। जल्द ही हम इन मुद्दों को नौकरी प्रोत्साहन प्रणाली के साथ संबोधित करेंगे। यहाँ "सुशासन" की कुंजी निहित है।

संदर्भ सूची

- Arora, Ramesh (2006),” Public Administration: A Fresh Perspective” Akash Publishers, Jaipur.

- Awasthi & Maheshwari (1982), "An Introduction to Public Administration" Deep & Deep Publication, Delhi.
- Bhghal, C.L & Yogindra Kumar, (2006), "Good governance: Issues Access Culture" Kaniksha Publication, New Delhi.
- Bull, Benedite and Dismount, M.C. Neil (2006), 'Developmental Issues in Global Governance" Routledge Publication, New York.
- Das, S.K. (1995), "Disempowerment of Indian Bureaucracy" Economic & Political Weekly. Vol. XXX No 2, January 14, 1995.
- Dayal Ishwar (1975), "New Perspective of Public Administration in India" Training Division, Department of Personnel and Administrative Reforms, July –Sept. 2007, New Delhi.
- Dey, Batak (1995), "Disempowerment of Indian Bureaucracy" Economic & Political Weekly, Vol. XXX No 2, Jan 14, 1995.
- Hazari, Shivam , Sharique Hussain Khan, Mayuresh Kumar Misra (2013), "Good governance and Human Rights in a Democracy" Paper presented in International Conference on Sustainable Development on Dec. 4-5, 2013 at Chandigarh Judicial Academy, Chandigarh.
- Issac N.Obasi (2006), " Globalization & Governance : Pressure for Constructive Administrative change," Journal of Rajasthan Institute of Public Administration- Jan 2006, Rajasthan Institute of Public Administration, Jaipur (Rajasthan)
- Munshi, Surender & Biju Paul Abraham (2004), "Good governance: Issue across Culture" Kaniksha Publications, Delhi.
- Mathur, Kuldeep (2008), "From Government to Governance: A Brief Survey of Indian Experience" National Book Trust, New Delhi.
- Medury, Uma (2007), "Good Governance & Pursuit of Transparency in Administration: Issues & Strategies' "Social Action – Vol. 59, Dec. 2010, New Delhi.
- Pankaj, Deep (2010), "Corruption, Transparency & Good Governance" Prentice Hall of India, New Delhi.
- Ray, Binayat (2013),"Sustainable Development & Good Governance Issues" Atlantic Publisher,Delhi.
- Sapru, R.K., & Yudhishthra Sapru, " Good Governance with Special Reference to India" The Indian Journal of Public Administration, Vol. LX No2 April-June 2014, Indian Institute of Public Administration, New Delhi.